an>

Title: Regarding disparity in pay and service benefits of Para-Military Forces as compared to Armed forces.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : महोदया, मैं आपका, सदन का और सरकार का ध्यान हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेज़ की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारे देश में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हैं, उनको फौज़ के मुकाबले कम सहुलियतें मिल रही हैं। अगर हम बीएसएफ की बात करें तो देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले बीएसएफ गोलियाँ खाती है। अगर सीआरपीएफ की बात करें तो कहीं कोई परेशानी हो या दंगे हों तो वहां सीआरपीएफ का जवान सबसे पहले गोलियाँ खाता है। पार्लियामेंट की सुरक्षा भी सीआरपीएफ ही कर रही है। अगर सीआईएसएफ की बात करें तो हमारे एयरपोर्ट्स, मैट्रो आदि सरकारी संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, उसके लिए वे वहां पर दिन-रात पहरा दे रहे हैं। अगर इन पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के एक कौंस्टेबल की बात करें तो फौज के मुकाबले उसकी तनख्वाह में 5000 रूपये प्रति महीने का अंतर है। अगर ऑफिसर लैवल की बात करें तो तकरीबन 22000 रूपये प्रति माह का फर्क है। अगर कौंस्टेबल की प्रमोशन की बात करें तो जो ओहदा 20 साल में फौज के जवान को मिलता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के कौंस्टेबल को उस लैवल तक पंहुचने में 29 साल लगते हैं। पिछले जनवरी 2011-जनवरी 2014 के बीच पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के तकरीबन 368 जवानों ने आत्महत्याएं की हैं क्योंकि अगर कैजुअल लीव की बात करें तो जहां फौज में 20 से 30 मिलती हैं तो यहां 15 ही मिलती हैं। अगर कैंटीनों की सहुलियतों की बात करें तो वह उनको कोई नहीं है, मैडिकल सहूलियतें बहुत कम हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्सेज़ फौज की तरह ही हमारे देश की एकता और अखंडता को एक रखने के लिए अपनी शहादतें दे रहे हैं। नक्सली एरिया में जनवरी, 2011 से जनवरी 2014 के बीच 371 पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के जवानों ने अपनी शहादतें दी हैं। मेरी सरकार से विनती है कि सरकार जोर दे कर यह व्यवस्था करे कि आने वाले पे कमीशन में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज़ की पे, उनकी सहूलियतें फौज के बराबर हो सके। आपके माध्यम से यही मेरी सरकार से गुजारिश है।